4. प्रोजेक्ट पैकेज योजना (आई०एच०बी०डी० सहित)	112.70	—	15.00
5. प्रोसेसिंग सुविधाओं का सृजन	20.00	—	—
6. कल्याणकारी पैकेज योजना	—	—	13.00
7. स्वास्थ्य पैकेज योजना	—	—	9.97
कुल :	132.70	—	100.97

गैर-योजना

1. जनता कपड़े पर सब्सिडी	409.54	475.93	291.07
2. हथकरघा कपड़े पर विशेष छूट	—	—	2.21
कुल :	409.54	475.93	293.29
कुल योग	542.24	475.93	394.25

बिहार के हथकरघा बुनकरों के लिये कल्याण योजनाएं

2214. **श्री एस. एस. अहलुवालिया :** क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राज्य सरकार के सहयोग से बिहार के हथकरघा बुनकरों के लिए कोई कल्याणकारी योजना बनाई है ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ; और

(घ) सरकार बिहार के हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए क्या कदम उठाने का विचार रखती है ?

वेंकटवस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी० स्वामी) : (क) जी हां

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बिहार सरकार को वर्ष 1992-93 के दौरान कार्यशाला-सह-आवास स्वास्थ्य पैकेज योजना और थ्रिफ्ट फंड योजना जैसी कल्याणकारी योजनाओं के अंतर्गत सहायता जारी की गई वर्ष 1993-94 के दौरान स्वास्थ्य पैकेज योजना और कार्यशाला सह-आवास योजन के अंतर्गत सहायता जारी की गई है

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता

हथकरघा क्षेत्र के लिए राज्य सरकारों को धनराशि का दिया जाना

2215. **श्री रामसिंह राठवा :** क्या वस्त्र, मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वर्ष 1992-93 में सरकार ने राज्यों को हथकरघों

के विकास के लिए 1991-92 की तुलना में कम धनराशि उपलब्ध कराई है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) यद्यपि गैर-प्लान योजनाओं के अंतर्गत वर्ष 1991-92 की तुलना में वर्ष 1992-93 के दौरान राज्य सरकारों को कम राशि दी गई है लेकिन प्लान योजनाओं के अंतर्गत उन्हें अधिक राशि दी गई ।

(ख) गैर-प्लान योजनाओं के अंतर्गत कम राशि इसलिए भी जारी की गई क्योंकि सरकार की नीति है कि जनता कपड़ा योजना को धीरे -धीरे समाप्त किया जाए और विपणन विकास सहायता के अंतर्गत राज्य सरकारें बराबर आधार पर अपना अंशदान नहीं दे पाई । प्लान योजनाओं में सहायता में वृद्धि इसलिए संभव हो पाई क्योंकि वर्ष 1991-92 के अन्तिम भाग और वर्ष 1992-93 के दौरान कई नई प्लान योजनाएं आरंभ की गई हैं । इन योजनाओं में प्रोजेक्ट पैकेज योजना एकीकृत हथकरघा ग्राम विकास योजना समूह बीमा योजना स्वास्थ्य पैकेज योजना और संबंधित कार्यशाला सह-आवास योजना शामिल हैं ।

Closure of ailing NTC units

2216. SHRI VIRENDRA KATARIA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) whether Government have decided to close down about 18 ailing National Textile Corporation Units in near future;

(b) whether Labour Unions have been consulted in this regard; and

(c) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) to (c) The Sub Committee of the Special Committee on National Textile Corporation, which includes representaiives of INTUC, NLO, BMS, HMS, AITUC and CITU, has accepted the Plan prepared by the Cotton Textile Research Associations for the modernisation of National Textile Corporation with the provisio that "restructuring with modernisation has to be done at each unit level".

Opening of fashion training centres

2217. SHRI VIREN J. SHAH:
SHRI PRAMOD MAHAJAN:
Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) wheher it is a fact that his Ministry propose to open fashion training centres in different parts of the country to widen the technical base of the garment industry to enable it to face stiff compitition in the fashion-conscious international market;

(b) if so, what are the details thereof and names of places where these fashion training centres are likely to be opened;

(c) by when these training centres are likely to be set up and at what cost; and

(d) what will be Government's share out of the total expenses proposed to be incurred in respect of these training centres?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF TEXTILES (SHRI G. VENKATSWAMY): (a) to (d) Government are examining the feasibility of setting up a few more institutes of fashion technology in important garment manufacturing centres by involving the concerned State Governments in raising the required resources and in managing the institutes. A final decision regarding the locations and cost sharing arrangement will be taken after discussions with the concerned State Governments.

Problems of Handloom Weavers

2218. SHRI KAMAL MORARKA: Will the Minister of TEXTILES be pleased to state:

(a) the number of workers employed in the handloom sector;